महत्वपूर्ण एवं खास

कैश बैंक का झांसा देकर 90 हजार की ठगी मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी में ऑनलाइन ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर ठगी से बचने पुलिस लगातार लोगों को जागरूक भी कर रही है। मगर, ठगों के जाल में लोग आसानी से आ जा रहे। ताजा मामला उरला थाना क्षेत्र का है। कैश बैक का लालच देकर ठग ने पहले एनी डेस्ट एप डाउनलोड करवाया उसके बाद खाते से 90 हजार रुपये पार कर दिए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, नंद किशोर मेहता ने ठगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए पीड़ित को फोन पे में 399 रुपये कैश बैक मिलने का झांसा दिया। इसके बाद एनी डेस्ट एप डाउनलोड करवा कर खाते से दो बार में 90 हजार रुपये पार कर दिए। पीड़ित की शिकायत पर उरला पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। उरला पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ शिकायत पीड़ित नंद किशोर मेहता ने की है।

नाबालिग को भगाकर ले जाने वाले संदेही पर केस दर्ज

महासमुंद (आरएनएस)। नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले एक संदेही युवक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामला सिंघोड़ा थाना क्षेत्र का मामला है। थाना से मिली जानकारी के अनुसार 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के पिता की रिपोर्ट पर आरोपी संदेही युवक ग्राम साहसपानी थाना सारंगढ़ जिला रायगढ़ निवासी रूपेश सूर्यवंशी के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। ये संदेही युवक उसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। इधर, पुलिस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर दोनों की पतासाजी में जुट गई है। आरोपी ने यह घटना 15-16 जुलाई की दरम्यानी रात को अंजाम दिया है।

मंडुआडीह रेलवे स्टेशन अब बनारस स्टेशन के नाम से जाना जाएगा

रायपुर (आरएनएस)। पूर्वोत्तर रेलवे बनारस रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस किया गया। इस स्टेशन का अंग्रेजी नाम बीएएनएआरएएस एवं कोड (बीएसबीएस) के और हिन्दी में बनारस के नाम जाना जाएगा। यह नाम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। रेल मंडल रायपुर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बनारस रेलवे के स्टेशन के प्लेटफार्मों पर बनारस के बोर्ड हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में भी लिखे गए हैं। बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी होने के कारण भारत के उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिणी राज्यों से ही नहीं विदेश के भक्त भी यहां आकर रमे रहते हैं । आध्यात्मिक मार्ग की तलाश में हजारों विदेशी भक्त प्रतिदिन काशी में रमे रहते हैं। घाटों पर इनका विचरण कौतूहल पैदा करता है । अब यहां आने वाले यात्रियों का जब शिव की नगरी के एक नए गौरव से परिचय होता है तो वह नई अनुभूति लेकर जा रहे हैं ।

एटीएम मशीन का शटर तोड़कर 2.20 लाख की चोरी, अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। एटीएम मशीन का शटर तोड़कर 2 लाख 20 हजार रुपये की करने की रिपोर्ट खमतराई थाने में दर्ज करायी गई है। मिली जानकारी के अनुसार अम्लेश्वर दुर्ग निवासी रुपेन्द्र कुमार साहू 31वर्ष ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि प्रार्थी टीएसआई प्राईवेट कंपनी रायपुर में जिला कार्यपालक मशीनरी के पद पर कार्यरत है। कंपनी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक का एटीएम मशीन कई स्थानों पर लगाया गया है। जिसमें एक एटीएम मशीन खमतराई ओव्हरब्रिज में लगा हुआ है। 17 जुलाई को दोपहर 3 बजे के करीब एटीएम मशीन में कैश डालने गए दीप ठाकुर खमतराई ओव्हरब्रिज गया था। तब पता चला कि एटीएम मशीन का शटर तोड़कर मशीन से 2 लाख 20 हजार रुपये अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया।

आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ जैविक राज्य के रूप में स्थापित होगा : मुख्यमंत्री

» **गोधन न्याय योजना के शानदार एक वर्ष पूर्णः पिछले वर्ष 20 जुलाई को हरेली से शुरू हुई थी योजना**

» **मुख्यमंत्री ने गोबर संग्राहकों, स्व-सहायता समूहों, गौठान समितियों और स्वावलंबी गौठानों को कुल 31.20 करोड़ रूपए की राशि का किया अंतरण**

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश में गोधन न्याय योजना प्रारंभ होने के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ जैविक राज्य के रूप में स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना ने गौपालक, किसानों के साथ-साथ गोबर बेचने वाले भूमिहीन लोगों को आय का एक नया जरिया उपलब्ध कराया है बल्कि इस योजना के माध्यम से महिला स्व सहायता समूहों की लगभग 80 हजार महिलाएं भी आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रही हैं। प्रदेश में गोधन न्याय योजना की शुरूआत पिछले वर्ष हरेली के त्यौहार के अवसर पर 20 जुलाई से प्रारंभ हुई थी। योजना के एक वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री ने पशुपालकों और प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

गोधन न्याय योजना प्रारंभ होने से लेकर एक वर्ष की अवधि में गोबर संग्राहकों से 48.77 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई तथा गोबर संग्राहकों को कुल 97 करोड़ 55 लाख रूपए की राशि का भुगतान किया गया। इसी तरह अब तक स्व-सहायता समूहों और गौठान समितियों को लाभांश की राशि के रूप में कुल 35 करोड़ 41 लाख रूपए का भुगतान किया गया। गोधन न्याय योजना से प्रदेश के एक लाख 71 हजार से अधिक पशुपालक लाभान्वित हो रहे हैं। लाभान्वित होने वालों में 76 हजार से अधिक भूमिहीन लोग हैं। गोधन न्याय योजना और सुराजी गांव योजना के तहत गौठानों में सामुदायिक बाड़ी, मशरूम उत्पादन, सब्जी उत्पादन, मुर्गीपालन, पशुपालन, मछली पालन, गोबर के दीये और गमले निर्माण, गौकाष्ठ निर्माण जैसी आर्थिक गतिविधियों से 8 हजार 874 महिला स्व-सहायता समूहों को लगभग 31 करोड़ 41 लाख रूपए की आय हुई है। प्रदेश में स्वीकृत 10 हजार 82 गौठानों में से 5883 गौठान सक्रिय हैं। इनमें से 1160 गौठान स्वावलंबी हो गए हैं।

मुख्यमंत्री ने आज कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर संग्रहण, स्व-सहायता समूहों, गौठान समितियों को लाभांश की राशि तथा प्रोत्साहन राशि के रूप में गौठान प्रबंधन समिति और स्वावलंबी गौठानों को कुल 31 करोड़ 20 लाख रूपए की राशि का अंतरण किया। इस राशि में से गोबर संग्राहकों के खाते में 43 लाख रूपए, महिला स्व-सहायता समूहों को लाभांश 2 करोड़ 66 लाख रूपए, गौठान समितियों को 3 करोड़ 69 लाख रूपए की राशि, प्रोत्साहन राशि के रूप में गौठान प्रबंधन समितियों को 23 करोड़ 28 लाख रूपए, स्वावलंबी गौठानों को एक करोड़ 14 लाख रूपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना बहुआयामी लाभ देने वाली योजना है। योजना के माध्यम से तैयार हो रही है वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से ना केवल भूमि की उर्वरता बढ़ेगी बल्कि हमें जैविक अनाज और जैविक कृषि उत्पाद भी मिलेंगे। आज रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की कीमतों और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। रासायनिक उर्वरकों की मांग के अनुरूप पर्याप्त आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है, ऐसे में वर्मी कंपोस्ट और गोमूत्र से निर्मित दवाइयों के उपयोग से कृषि की लागत कम होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना के जरिए खरीदे गए गोबर से लगभग 9 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट का उत्पादन महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया गया है और सहकारिता के माध्यम से इस मात्रा का 70 प्रतिशत वर्मी कंपोस्ट तथा सुपर कंपोस्ट का वितरण भी किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश में किसानों का खेती की ओर रूझान बढ़ा है। गोधन न्याय योजना से डेयरी को भी लाभ हो रहा है। पिछले एक वर्ष में गौठानों का निर्माण किया गया। गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन की व्यवस्था पशुओं के लिए कोटना, गौठानों में घेरा की व्यवस्था की गई।

सात बच्चों की मौत की बात झूठी, जिला अस्पताल प्रबंधन का दावा

रायपुर (आरएनएस)। जिला अस्पताल में 7 बच्चों की मौत मामले के बाद प्रबंधन ने फ्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौत की जानकारी को भ्रामक बताया।

नर्सरी इंचार्ज डॉ ओंकार खंडवाल के मुताबिक बीते 24 घंटे में केवल दो शिशुओं की मौत हुई है। डॉ खंडवाल ने ऑक्सीजन की कमी को खारिज कर हुए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होने की बात कही। उन्होंने आगे बताया कि मंगलवार को 15 से ज्यादा बच्चे वेंटिलेटर पर थे। अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो सभी की मृत्यु होती, ना कि 1 या 2 की। उन्होंने गरियाबंद के शिशु को लेकर भी भ्रामक जानकारी देने की बात कही। खंडवाल के मुताबिक गरियाबंद का शिशु प्रीमेच्योर चाइल्ड था, वह अभी भी जिंदा है। उसके लिए हमने बहुत ही महंगी दवाई का इस्तेमाल कर उसे बचाया है। डॉक्टर के मुताबिक शिशु के पिता के ने नशे में धुत होकर जमकर हंगामा किया। फिलहाल हमारे पास 37 बच्चे भर्ती हैं, 23 बच्चों की स्थिति गंभीर है।

पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने थाली पीटकर किया प्रदर्शन

बिलासपुर (आरएनएस)। शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 1 के द्वारा पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में थाली पीठ कर विरोध किया प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के आव्हान पर एवं जिला शहर कांग्रेस कमेटी बिलासपुर के निर्देशानुसार शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 01अध्यक्ष जावेद मेमन के तत्वाधान में पेट्रोल डीजल के साथ ही रोजमर्रा के वस्तुओ की बढ़ती मंहगाई के विरोध में थाली व अन्य बर्तन पीटकर विरोध दर्ज कराना है केंद्रीय उत्पाद शुल्क कम करने की मांग करेंगे और नेहरू चैक. पेट्रोल पम्प के पास महंगाई के विरोध में आंदोलन किया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष अटल वास्तव ने कहा कोरोनाकाल मे जहां सभी वर्ग परेशान हैं आम जनों के लिए राहत कार्य चल रहा है। केंद्र की मोदी सरकार गरीबों को जेब काटने में लगी हुई है। जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी ने कहा है केंद्र की मोदी सरकार ने महंगाई की सारी सीमाये लाँघ दी है। सरकार ने आम आदमी का विश्वास खो दिया है। शहर अध्यक्ष प्रमोद ने कहा की आमजन इस महंगाई से बहुत परेशान हैं पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से खाद्य वस्तुएं महंगी हो रही है। प्रदेश प्रवक्ता अभय नारायण राय ने कहा कि महंगाई से आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है इस कमरतोड़ महंगाई से आम आदमी त्रस्त हो गया है। महापौर रामशरण यादव, जिला पंचायत के अध्यक्ष अरुण सिंह चैहान ने कहा है कि केंद्र सरकार आपदा मैं अवसर तलाश रही है। जावेद मेमन ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज नेहरू चैक पेट्रोल पंप के पास थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आज धरना प्रदर्शन में विधायक प्रत्याशी राजेंद्र शुक्ला, पूर्व विधायक दिलीप लहरिया, सभापति शेख नजरुद्दीन, पूर्व ब्लाक अध्यक्ष तैयब हुसैन, पूर्व शहर अध्यक्ष नरेंद्र बोलर, रविंद्र सिंह, अकबर खान, नसीम खान, सुधांशु मिश्रा, रामाशंकर बघेल, विनोद साहू, अरविंद शुक्ला, रिजवान खान, रमजान गोरी, सोहेल अहमद, राजू यादव, वकार खान एवं बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित थे।

बालको देश के गैर सूचीबद्ध शीर्ष 150 कंपनियों में शामिल

कोरबा (आरएनएस)। वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ;बालकोद्ध को डन एंड ब्रैडस्ट्रीट ने देश के शीर्ष 150 गैर सूचीबद्ध कंपनियों की सूची में शामिल किया है। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट ने वर्ष 2021 के लिए देश की शीर्ष 500 कंपनियों की सूची जारी की है। सूची में उन कंपनियों को शामिल किया गया है जो पर्यावरण, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा गवर्नेंस के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए व्यवसाय को नए आयाम दे रहे हैं।

डन एंड ब्रैडस्ट्रीट ने भारत के शीर्ष 500 कंपनीष् की अपनी सूची में विभिन्न क्षेत्रों से देश के उन प्रमुख कंपनियों को शामिल किया है जो अर्थव्यवस्था की मजबूती में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस वर्ष की थीम है . ष्लेइंग द फाउंडेशन फॉर एन ईएसजी रेडी कॉरपोरेट इंडिया। विश्वस्तरीय प्रबंधन, उच्च गुणवत्ता के एल्यूमिनियम उत्पादन, ग्राहक संतुष्टि, नवाचार, सामुदायिक विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, गवर्नेंस, कुल आय, लाभप्रदता, बाजार पूंजीकरण आदि मानदंडों के आधार डन एंड ब्रैडस्ट्रीट की सूची में बालको को स्थान मिला।

बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक अभिजीत पति कहते हैं कि ऐसे सम्मान पर्यावरण, सामुदायिक उत्तरदायित्व एवं गवर्नेंस के मानदंडों के प्रति बालको के मनोबल को मजबूती देते है। औद्योगिक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण प्रबंधन, सामुदायिक विकास तथा बेहतरीन प्रशासन के प्रति बालको कटिबद्ध है। देश की सतत उन्नति में योगदान के लिए बालको ने अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकों को बढ़ावा दिया है।

कोरबा स्थित होटल आशीर्वाद.इन के सीएमडी नवीन अरोरा ने बालको के उत्कृष्ट पर्यावरण प्रबंधन की प्रशंसा की है। अरोरा कहते हैं कि बालको ने देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, विश्वस्तरीय प्रचालन, पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। उन्होंने बालको के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं।

सामुदायिक विकास के क्षेत्र में बालको ने जिला प्रशासन और स्थानीय जन प्रतिनिधियों के समन्वयन में जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई है। स्थानीय स्तर पर ही 5000 से अधिक एमएसएमई बालको की प्रगति से जुड़े हैं। शून्य क्षति, शून्य अपशिष्ट, शून्य उत्सर्जन, नीति के अनुरुप बालको व्यवसाय के उच्च मानदंडों का पालन करता है। प्रचालन क्षेत्र से लगे गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना विकास की परियोजनाओं से जरूरतमंदों को विकास की मुख्यधारा से जुड़ने में मदद मिल रही है। साढ़े पांच दशकों में बालको की भागीदारी से लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं।

बीएसएफके जवान ने खुद को गोलीमारकर की आत्महत्या

कांकेर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले के कोड़ेकुरसी थाना क्षेत्र के करकापाल में बीएसएफके जवान ने कैम्प में खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। बीएसएफ जवान का नाम लक्ष्मण बताया जा रहा है. जबकि कांकेर एसपी शलभ सिन्हा ने घटना की पुष्टि की है। यह घटना मंलगवार को घटी। यही नहीं, जवान लक्ष्मण ने अपनी रायफल से खुद को गोली मार ली और गोली की आवाज से कैम्प में अफरा तफरी मच गई थी।

घटना के बाद साथी जवानों और बीएसएफके अधिकारियों ने जवान की गंभीर स्थिति को देखते हुए तत्काल जिला पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद जवान को हेलीकॉप्टर से रायपुर रेफर किया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बीएसएफ जवान लक्ष्मण ने खुद को गोली क्यों मारी, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है. जबकि बीएसएफ के अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं।

हाथियों ने उत्पात मचाते खोडरी में दो परिवार को किया बेघर

कोरबा (आरएनएस)। जिले के पसान रेंज में उत्पात मचा रहे दंतैल हाथियों के दल ने बीती रात मरवाही रेंज का रूख कर लिया। आज सुबह इन हाथियों को रेंज के भठियार जंगल में विचरण करते हुए देखा गया। इसकी सूचना मरवाही रेंजर को दिए जाने पर वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने निगरानी शुरू कर दी है। वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक हाथियों ने रात 11 बजे के लगभग पसान की सीमा को पार किया और मरवाही परिक्षेत्र में प्रवेश किया। इस दौरान वन विभाग द्वारा लगातार हाथियों की निगरानी की जाती रही। हाथियों ने मरवाही जाने से पहले पसान के खोडरी गांव में पहुंच कर भारी उत्पात मचाया।

इस दौरान दंतैल हाथियों ने प्रभात व जवाहर लाल नामक दो ग्रामीणों के सूनसान इलाके में स्थित मकानों को निशाना बनाते हुए क्षतिग्रस्त कर दिया। जिस समय हाथियों ने यहां धावा बोला, घर में कोई भी सदस्य मौजूद नहीं थे। हाथियों के खोडरी पहुंचने की भनक लगते ही वन विभाग का अमला गांव पहुंचकर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था। हाथियों ने दो किसानों के थरहे को भी नुकसान पहुंचाया है। आज सुबह वन विभाग के कर्मचारी व अधिकारी फिर खोडरी पहुंचे और रात में हाथियों द्वारा किये गए नुकसानी का आंकलन करने के साथ ही रिपोर्ट तैयार की। अधिकारियों के अनुसार हाथी पीड़ितों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा। इसके लिए प्रकरण तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है, जिसे डीएफओ के समक्ष भेजा जाएगा, जहां से स्वीकृति मिलने के बाद पीड़ितों को मुआवजा का भुगतान होगा। इससे पहले हाथियों ने पसान रेंज में दो दिनों तक भारी उत्पात मचाकर वन विभाग एवं ग्रामीणों के नाकों में दम कर रखाा था।

उत्पाती दंतैल हाथियों के मरवाही परिक्षेत्र में जाने से पसान के वन अमले ने कुछ राहत महसूस की है। इधर कोरबा वन मंडल के जंगलों में मौजूद दंतैल करतला के तुर्रीकटरा जंगल से आगे बढ़कर कोरबा रेंज पहुंच गया है। इस दंतैल को यहां के भेलवाटार बीट के सकदुकला गांव के जंगल में आज सुबह देखा गया। दंतैल के कोरबा रेंज पहुंचने की सूचना पर वन अमला मौके पर पहुंचकर लोनर की निगरानी में जुट गया है। कुदमुरा रेंज में भी एक दंतैल घूम रहा है। इस दंतैल ने फिलहाल यहां कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कुछ सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी सकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूर्धन्य विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए ....
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

कोविड संक्रमण से सुरक्षित रखने टीकाकरण की सलाह

रायपुर (आरएनएस)। भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा गर्भवती महिलाओ को कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में दिशा-निर्देश प्राप्त हुए तथा नेशनल टेक्नीकल एडवायजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाईजेशन एवं एन.ई.जी.वी.ए.सी द्वारा अनुशंसा की गई हैं। अतः विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा तथा विभिन्न स्टेक होल्डर्स के सहयोग से भारत सरकार के द्वारा गर्भवती महिलाओं के कोविड-19 टीकाकरण की अनुमति प्रदान की गई है।

मुख्य जिला एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मीरा बघेल ने बताया कि इस संबंध में गत दिनों ऑन लाईन उन्मूखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसके तहत गर्भवती महिला के कोविड-19 टीकाकरण हेतु जारी दिशा-निर्देशानुसार गर्भावस्था की किसी भी अवधि में सभी गर्भवती महिलाएं (प्रथम तिमाही, द्वितीय माह, तृतीय) कोविड टीकाकरण करवा सकती हैं। गर्भवती को लगने वाले टी.डी वैक्सिन के साथ या टी.डी लगने के 15 दिन बाद भी लगाया जा सकता है। अत्याधिक जटिलता वाले गर्भवती माता अपने चिकित्सक से परामर्श लेकर कोविड-19 का टीकाकरण करवा सकती हैं।

90 प्रतिशत प्रकरणों में गर्भवती माताओ को घर पर रखकर ठीक किया जा सकता है, किन्तु कुछ प्रकरण में गर्भवती महिला की स्थिति बहुत जल्दी गंभीर हो सकती हैं। अतः ऐसे स्थिति में उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है, नहीं तो विपरित परिणाम का जोखिम ज्यादा रहता हैं। उदाहरण के रूप में ऐसे समय सिजेरियन की जरूरत पड़ सकती हैं, समय से पूर्व डिलवरी हो सकती हैं, मृत्यु भी हो सकती हैं। उपरोक्त समस्त समस्या को टीका लगा के जोखिम से बचा जा सकता है।

गर्भवती महिलाओं को भी टीकाकरण के बाद कोविड व्यवहारों का पालन करना हैं। कोविड टीकाकरण के बाद उन्हें भी आम लोगों की तरह किसी-किसी में बुखार, इंजेक्शन वाले स्थान में दर्द, सूजन, बदन दर्द इत्यादि लक्षण दिखते है जो सामान्यतः 2-3 दिनो में ठीक हो जाते हैं।

उन गर्भवतीयों को टीका नहीं लगाना चाहिए जिनका पूर्व में प्रथम टीका लगने के बाद जिसे कोई दुष्प्रभाव हुआ हो या उन्हें किसी भी अन्य टीका से रियेक्शन हुआ हो या ऐसी गर्भवती माता जो वर्तमान में काविड-19 से ग्रसित हो और जो उपचारित हों।

गर्भवती होने के पहले महिला यदि कोविड पॉजिटिव होती है, तो ठीक होने के 03 माह या 84 दिन बाद प्रथम खुराक के बाद शेड्यूल के हिसाब से दुसरी खुराक दिया जा सकता है। गर्भवस्था के दौरान अगर महिला कोविड पाजिटिव हो गई है या तो उसे पहला टीका लगा है या कोई टीका नही लगा है, ऐसी स्थिति में डिलवरी तक टीका न लगाये एवं जंचकी के बाद ही उसे टीका लगवाने की सलाह दी गई है।